

इंडस्ट्री

सस्ता पड़ेगा
कच्चा माल

स्क्रेप पॉलिसी से ऑटो इंडस्ट्री में 50 हजार जॉब, लागत 30% घटेगी

■ नई स्क्रेप पॉलिसी से 10 हजार करोड़ का निवेश, 15 दिन में आया योजना का ब्योरा

■ मेगा टेक्सटाइल स्कीम लॉन्च, अगले 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे

■ स्टील पर कस्टम ड्यूटी कम होने से कारों की लागत में और भी कमी आने की उम्मीद

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

वित्त मंत्री ने बजट में देश की दो बड़ी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल पर जमकर कृपा बरसाई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बरसों पुरानी मांग स्क्रेप पॉलिसी को सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। इससे ऑटो इंडस्ट्री में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश, 50 हजार नई नौकरियां आएंगी, जबकि इसकी वजह से कच्चा माल सस्ता होने से कारों की लागत भी 30 फीसदी कम हो जाएगी। स्टील में ड्यूटी कम होने का फायदा भी ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा। वहीं, सरकार ने अगले तीन साल में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने का भी ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्क्रेप पॉलिसी में 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कर्मशियल वाहनों को स्क्रेप के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार वर्तमान 4.50 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में वे विस्तृत ऐलान करेंगे। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के प्रेसिडेंट विकेश गुलाटी के मुताबिक, कुल 37 लाख कर्मशियल और 52 लाख पर्सनल कारें 20 साल से पुरानी हैं। इसमें से 3.7 लाख कर्मशियल और 2.6 लाख पर्सनल व्हीकल स्क्रेप के दायरे में आएंगे। इधर, टेक्सटाइल के लिए ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि तीन साल में देश में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल को मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। ये पार्क पीएलआई स्कीम से अलग होंगे। इसके अलावा, बजट में नायलॉन यार्न पर आयात शुल्क को 7.5 फीसदी से घटा 5 फीसदी कर दिया है।



सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाना और एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रेपिंग नीति सहित कई स्वागत योग्य घोषणाएं की गई हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। - गुंटेर बुशेक, सीईओ एव एमडी टाटा मोटर्स

सूरत के साड़ी कारोबारियों की आस बंधी

...पर पॉलिस्टर पर ड्यूटी न घटने से निराशा

■ सूरत के टेक्सटाइल व्यापारियों की उम्मीद थी कि बजट में पॉलिस्टर यार्न पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी। इससे लागत कम हो सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

■ एक साड़ी ब्रांड लक्ष्मीपति के मालिक कहते हैं कि रोज 4 करोड़ मीटर पॉलिस्टर बनता है। इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से लोकल निर्माता 60% भाव बढ़ा चुके हैं।

■ हालांकि नाइलॉन यार्न पर ड्यूटी घटने से निर्माताओं को राहत है। व्यापारियों कहते हैं उन्हें डर था कि सरकार अतिरिक्त सेस लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

■ टेक्सटाइल पार्क से भी सूरत को फायदा होगा। ऐसे पार्क में गारमेंट हब बनेगा और प्रोसेसर्स पार्क बनेगा। हालांकि अभी यह तय होना है कि यह कहाँ बनेगा।

उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई

लघु उद्योगों से खरीदी का नियम नहीं

1. एनसीएलटी के जरिए डिफॉल्ट सीमा एक करोड़ से कम कर 5-10 लाख होने की आस रही अधूरी।

2. 80 जेजेए के तहत कटौती प्रति कर्मचारी 50 हजार प्रति माह होने की उम्मीद पूरी नहीं हुई।

3. डिजिटल पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार होना चाहिए था, लेकिन बजट में कोई घोषणा नहीं की।

4. 25% सरकारी खरीद लघु उद्योगों से करने का नियम राज्य सरकारों पर लागू करने पर बात नहीं।

ऑटोमोबाइल

लागत घटेगी, वाहन सस्ते

■ **फिटनेस टेस्ट:** 20 साल से पुराने निजी और 15 साल से पुराने कर्मशियल वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। योग्य न पाए जाने पर इन्हें स्क्रेप में भेजना होगा।

■ **ऐसे 6.3 लाख वाहन:** फाडा सीईओ सहर्ष दमानी ने बताया कि 1990 को बेस मानें तो देश में 37 लाख कर्मशियल (सीवी) और 52 लाख पर्सनल व्हीकल (पीवी) बिके हैं। इनमें से 10% सीवी और 5% पीवी अब भी चल रहे हैं। फिटनेस टेस्ट होने पर ये वाहन बाहर हो सकते हैं।

■ **लागत घटेगी:** एक्सेसरीज पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से गाड़ियों की लागत पर 5 से 10% असर पड़ेगा। स्टील पर कस्टम ड्यूटी 7.5% घटने से गाड़ियों की इनपुट लागत कम होगी।

टेक्सटाइल

विश्व स्तर पर टक्कर देंगे...

■ **एकीकृत सुविधा:** 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। यहां सभी तरह की एकीकृत सुविधाएं मिलेंगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन नुकसान कम हो।

■ **सबसे ज्यादा बजट:** कपड़ा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल (मित्रा) पार्क स्कीम लाने की बात कही थी। 1,000 एकड़ में ऐसे 59 पार्क बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 22 तैयार हो चुके हैं। यहां शोध-अनुसंधान के साथ ही अत्याधुनिक लैब की भी सुविधा मिलेगी।

■ **बजट बढ़ाया:** कपड़ा मंत्रालय को 3631 करोड़ दिए हैं। यह पिछले साल के बजट 3514 करोड़ रु. से अधिक है। 2025-26 तक उद्योग का आकार 300 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है।

स्टार्टअप

टैक्स हॉलिडे एक साल बढ़ा

■ **राहत मिली:** स्टार्टअप कैपिटल गैन्स से छूट 31 मार्च 2022 तक उठा सकेगा। 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कारोबार वाले स्टार्टअप को 3 साल के लिए कर छूट।

■ **कानूनी खर्च घटेगा:** एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स आधारित एमसीए 21 संस्करण 3.0 शुरू होगी। सबसे बड़े टेक स्टार्टअप क्यूबिकट्री के फाउंडर सीईओ हितेश जीरावाला ने बताया, इससे ई-सुरक्षा की शुरुआत होगी। कंपनियों और लोगों के लिए कानूनी खर्चों में कमी आएगी।

■ **ईएसओपी स्कीम:** एंजलोज स्टॉक ओनरशिप प्लान में राहत दी है। एंजलोज को तभी टैक्स चुकाना होगा, जब वह शेयर बेचेगा। प्लान जारी होने पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा।